

# प्रयाग दर्पण

वर्ष : 09

अंक : 79

प्रयागराज, सोमवार 19 जून , 2023

हिन्दी दैनिक

पृष्ठ-4

मूल्य : 3 रुपया

## भारत लोकतंत्र की जननी है पीएम मोदी ने फिर याद किया इमरजेंसी का दौर, बोले- मन सिंह उठता है

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का 'काला दौर' करार देते हुए रविवार को कहा कि उस दौरान लोकतंत्र के समर्थकों पर जो अत्याचार किए गए और उन्हें जिस प्रकार की यातनाएं दी गईं, उसे याद करने भर से आज भी मन सिंह उठता है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 102वीं कड़ी में अपने विचार साझा करते हुए मोदी ने कहा कि भारत 'लोकतंत्र की जननी' है, जो लोकतांत्रिक आदर्शों और संविधान को सर्वोपरि मानता है, लिहाजा 25 जून की तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत में 1975 में आपातकाल लगाया गया था। इसे भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की बड़ी घटना माना जाता है। मोदी ने कहा, "भारत लोकतंत्र की जननी है। हम, अपने लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोपरि मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए, हम 25 जून को भी कभी भुला नहीं सकते। यह वही दिन है जब हमारे देश पर आपातकाल थोपा गया था। पीएम मोदी ने कहा, "यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने आपातकाल का पूरी



ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गईं कि आज भी मन सिंह उठता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश जब आजादी के 75 वर्ष से सौवें वर्ष की तरफ बढ़ रहा है, तो आजादी को खतरे में डालने वाले आपातकाल के अपराधों का अवलोकन जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे आज की युवा पीढ़ी को लोकतंत्र के मायने तथा उसकी अहमियत समझने में और ज्यादा

आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भी उल्लेख किया और देशवासियों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं, तो 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। योग में तो वैसे भी ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं

होती है। जब आप योग से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री इस वर्ष योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य इसके कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। इसकी सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए, दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी।

### 23 जून के बाद फिर होगा नीतीश कैबिनेट का विस्तार, राजद और कांग्रेस कोटे से बनेंगे मंत्री



**पटना।** बिहार में 23 जून के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें राजद और कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दी है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद एकबार फिर से बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें कांग्रेस और राजद कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बता दें कि राजद के दो मंत्रियों कार्तिकेय कुमार और सुधाकर सिंह ने अलग-अलग पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान व्यापक हिंसा में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

कारण हुई। भाजपा पश्चिम बंगाल में हर अपराध को एक राजनीतिक रंग देती है और इसे पंचायत चुनावों से जोड़ती है। पुलिस ने बताया कि मालदा जिले के शुजापुर इलाके में टीएमसी उम्मीदवार मुस्तफा शेख पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। उन्होंने बताया कि शेख को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राज्य मंत्री

सबीना यास्मीन के अनुसार, टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस में शामिल होने वाले टीएमसी के पूर्व कार्यकर्ता शेख पर हमले के पीछे हैं। आठ जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान व्यापक हिंसा में राज्य के विभिन्न हिस्सों में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

संबंधित यात्रा और आवास संबंधी जरूरतों के लिए लगभग 850 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है। इसलिए इसका व्यवसाय की वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ना तय है। काचरु रैंडिसन होटल ग्रुप के मानद चेयरमैन और प्रधान सलाहकार (दक्षिण एशिया) भी हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व में वृद्धि के साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। आतिथ्य क्षेत्र के 5.5 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ने की उम्मीद है। जी-20 अध्यक्षता वर्ष में भारत देशभर में 59 विभिन्न स्थानों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी करेगा। इसमें 20 देशों के 1.5 लाख से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। शैले होटल्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ संजय सेठी ने कहा, 'भारत की अध्यक्षता में जी-20 शिखर सम्मेलन से देश को काफी बढ़ावा मिलेगा।' उन्होंने कहा कि इसके लाभ एक साल तक सीमित नहीं रहेंगे और इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखने को मिलेगा।



के उपाध्यक्ष के बी काचरु ने बताया कि जिन शहरों में जी-20 की बैठकों का होगा, वहां मांग तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही 2022 की अंतिम तिमाही से प्रमुख व्यापारिक शहरों में

पांच सितारा होटलों के कमरों का किराया लगभग 20 प्रतिशत बढ़ा है। ये रुझान आने वाले महीनों में जारी है। इसके साथ ही 2022 की अंतिम तिमाही से प्रमुख व्यापारिक शहरों में

**दिल्ली बहनों की हत्या: वीडियो में खुलेआम फायरिंग करते दिखाई दे रहे हमलावर नई दिल्ली।** दिल्ली के आर.के. पुरम इलाके में दो बहनों पर हुए हमले का एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ है। इसमें हमलावर बेखौफ होकर अंधाधुंध फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में हमलावरों को दो बहनों पिंकी (30) और ज्योति (29) पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है, जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही थीं। वीडियो में घटनास्थल पर जमा भीड़ को भी दिखाया गया है। मौके पर इतने लोगों के होने के बावजूद हमलावर फायरिंग करते हुए भागने में सफल रहे। अधिकारियों ने कहा कि बाद में उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और गश्त भी की जा रही है। मामले में आर्मस एक्ट सहित हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच के लिए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों का मशतक के भाई से आर्थिक मामले को लेकर विवाद था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति की आलोचना की और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

## विपक्ष के बहाने भ्रष्टाचारी, वंशवादी दलों को जुटा रहे नीतीश कुमार : सुशील मोदी

**पटना।** बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने वाले विपक्षी दलों के बैठक के पूर्व भाजपा ने बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्षी एकता के नाम पर भ्रष्टाचार में डूबे वंशवादी दलों की बैठक बुलाई गई है और ये सभी दल केवल अपनी-अपनी दुकान बचाने के लिए एक-साथ दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जुटान का न देशहित, लोकतंत्र और विकास से कोई वास्ता है और न इनमें से कोई दल अपने प्रभाव वाले राज्य में दूसरे गैर-भाजपा दल से हाथ मिलाते को तैयार हैं।



मोदी ने कहा कि जिन दलों ने इसमें भाग लेने की सहमति दी है, उनमें कांग्रेस, राजद, सपा, टीएमसी, माकपा, झामुमो, द्रमुक सहित दर्जन-भर पार्टियां ऐसी हैं, जिनका नेतृत्व किसी एक परिवार के हाथ में है और जिनके बड़े नेता भ्रष्टाचार के मामलों में जेल या बेल के बीच व्यवस्था की स्थिति की आलोचना की प्रमुख लालू प्रसाद चारा घोटाला के सभी मामलों में सजायापता होकर

जमानत पर हैं। राजद में दूसरी पीढ़ी के नेता नौकरी के बदले जमीन मामले में कभी भी जेल जा सकते हैं? मोदी ने कहा कि दो दिन पहले द्रमुक सरकार के बिजली मंत्री गिरपतार हुए। आप, टीएमसी, एनसीपी के दो-दो मंत्री जेल में हैं या बेल पर। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा-विरोधी दल राष्ट्रीय स्तर एक होने का नाटक

करते हैं और दूसरी तरफ अपने-अपने राज्य में एक-दूसरे को मिटाने पर तुले हैं। यह कैसी एकता है? उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसी विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है, जो केवल भ्रष्टाचार और वंशवाद के समर्थन में है। 23 जून को नीतीश कुमार जेपी की कर्मभूमि पटना को कलंकित करने वाले हैं।

## युवाओं के रोजगार के सपने थे पीएसयू, अब घटी दो लाख नौकरियां : राहुल गांधी

**नई दिल्ली।** कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में दो लाख से अधिक नौकरियों में गिरावट को लेकर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भारत का गौरव हुआ करता था और रोजगार के लिए हर युवा का सपना होता था। लेकिन चंद पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने हिंदी में एक टवीट में कहा, पीएसयू भारत का गौरव हुआ करते थे और रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करते थे। लेकिन ये आज सरकार की प्राथमिकता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि देश में पीएसयू में रोजगार 2014 में 16.9 लाख से घटकर 2022 में केवल 14.6 लाख रह गया है। उन्होंने कहा, क्या विकासशील देश में रोजगार घटना है? सरकार पर कटाख करते हुए, वायनाड के पूर्व लोकसभा सांसद ने कहा, जिन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झूठा वादा किया था, उन्होंने 2 लाख से अधिक



नौकरियों को समाप्त कर दिया। इसके अलावा, इन संस्थानों में संविदा भर्ती लगभग दोगुनी हो गई है। क्या यह इन कंपनियों के निजीकरण की साजिश है? राहुल ने कहा, उद्योगपतियों के ऋण माफ किए गए, और सार्वजनिक उपक्रमों से सरकारी नौकरियां खत्म हो गईं। यह कैसा अमरुत काल है? यदि यह वास्तव में अमरुत काल है तो नौकरियां इस तरह क्यों गायब हो

रही हैं? इस सरकार के तहत देश रिकॉर्ड बेरोजगारी से जूझ रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, चंद पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लाखों नौजवानों की उम्मीदों को कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा, यदि भारत के पीएसयू को सरकार से सही वातावरण और समर्थन मिलता है, तो वे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों को बढ़ाने में सक्षम हैं। पीएसयू देश और

देशवासियों की संपत्ति हैं, उन्हें बढ़ावा देना होगा ताकि वे भारत के प्रगति पथ को मजबूत कर सकें। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने भी पीएसयू में सरकारी नौकरियों में कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। 40 वर्षों में देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी दर को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार की आलोचना करती रही है।

देशवासियों की संपत्ति हैं, उन्हें बढ़ावा देना होगा ताकि वे भारत के प्रगति पथ को मजबूत कर सकें। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने भी पीएसयू में सरकारी नौकरियों में कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। 40 वर्षों में देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी दर को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार की आलोचना करती रही है।

### संसदीय बहस एवं चर्चा की गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी : खडगे

**मुंबई/नई दिल्ली।** कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए संसद में बहस और चर्चा की गुणवत्ता बढ़ाने को जरूरी बताते हुए कहा है कि सहिष्णुता और स्वस्थ विचार विमर्श से लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है। श्री खडगे ने मुंबई में आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के लिए भेजे अपने संदेश में कहा कि इस तरह के आयोजन को लोकतंत्र के लिए विशेष अवसर बताया कि ऐसे कार्यक्रमों से देशभर के जनप्रतिनिधियों को एक साझा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वे अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। संसदीय बहसों और चर्चाओं की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाने को अत्यंत आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र की चौपाल में जनता की आवाज निडर होकर उठानी चाहिए और उस पर स्वस्थ तरीके से विचार-विमर्श भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे माहौल को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए कि विचारों पर स्वस्थ बहस हो और हमारे विधायकों का सामूहिक ज्ञान हमारी नीतियों और कानूनों को जन भावना के अनुरूप आकार दे। विधायिका लोकतंत्र की आधारशिला है और उसे ही सुनिश्चित करना है कि कार्यपालिका नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। कांग्रेस अध्यक्ष ने नागरिकों के हितों की रक्षा के वास्ते जांच और संतुलन की मजबूत व्यवस्था को जरूरी बताया और कहा कि यह व्यवस्था करना विधायकों की जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभव पर वह कह सकते हैं कि इस कार्य का निष्पादन अत्यंत परिश्रमसाध्य लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए हम सबको यह याद रखना जरूरी है कि लोकतंत्र केवल स्वस्थ बहस, विचार-विमर्श और चर्चा के माध्यम से ही कार्य कर सकता है। श्री खडगे ने लोकतंत्र की मजबूती के संबंध में अपने संदेश में पंडित नेहरू को उद्धृत करते हुए कहा, 'लोकतंत्र का अर्थ सहिष्णुता है। सहिष्णुता न केवल उन लोगों के लिए है जो हमसे सहमत हैं बल्कि उन लोगों के लिए भी हैं जो हमसे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना है कि इस तरह के सम्मेलन विधायकों को सहयोग करने, एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और हमारे राष्ट्र की प्रगति और भलाई में योगदान करने के लिए आवश्यक हैं।

### तो एक और मन की बात लेकिन 'मणिपुर पर मौन कांग्रेस ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

**नई दिल्ली।** कांग्रेस ने रविवार को मणिपुर की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि एक और 'मन की बात, लेकिन 'मणिपुर पर मौन हैं। मणिपुर में करीब एक महीने पहले मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'तो एक और 'मन की बात लेकिन 'मणिपुर पर मौन। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए प्रधानमंत्री ने खुद की पीठ थपथपाई। पूरी तरह से मानव निर्मित उस मानवीय आपदा का क्या, जिसका सामना मणिपुर कर रहा है। रमेश ने ट्विटर पर कहा, 'अभी भी उनकी (प्रधानमंत्री) ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर-लेखापरीक्षा योग्य 'पीएम-केयर फंड है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की भी परवाह है, यही असली सवाल है। इससे पहले रविवार को रेडियो पर प्रसारित 'मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो ताकत भारत ने वर्षों से विकसित की है, वह आज मिसाल बन रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर के 10 विपक्षी दलों ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की 'धुप्पी को लेकर सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा शांति की अपील करने का आग्रह किया था।

मणिपुर पर मौन हैं। मणिपुर में करीब एक महीने पहले मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'तो एक और 'मन की बात लेकिन 'मणिपुर पर मौन। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए प्रधानमंत्री ने खुद की पीठ थपथपाई। पूरी तरह से मानव निर्मित उस मानवीय आपदा का क्या, जिसका सामना मणिपुर कर रहा है। रमेश ने ट्विटर पर कहा, 'अभी भी उनकी (प्रधानमंत्री) ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर-लेखापरीक्षा योग्य 'पीएम-केयर फंड है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की भी परवाह है, यही असली सवाल है। इससे पहले रविवार को रेडियो पर प्रसारित 'मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो ताकत भारत ने वर्षों से विकसित की है, वह आज मिसाल बन रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर के 10 विपक्षी दलों ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की 'धुप्पी को लेकर सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा शांति की अपील करने का आग्रह किया था।

मणिपुर पर मौन हैं। मणिपुर में करीब एक महीने पहले मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'तो एक और 'मन की बात लेकिन 'मणिपुर पर मौन। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए प्रधानमंत्री ने खुद की पीठ थपथपाई। पूरी तरह से मानव निर्मित उस मानवीय आपदा का क्या, जिसका सामना मणिपुर कर रहा है। रमेश ने ट्विटर पर कहा, 'अभी भी उनकी (प्रधानमंत्री) ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर-लेखापरीक्षा योग्य 'पीएम-केयर फंड है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की भी परवाह है, यही असली सवाल है। इससे पहले रविवार को रेडियो पर प्रसारित 'मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो ताकत भारत ने वर्षों से विकसित की है, वह आज मिसाल बन रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर के 10 विपक्षी दलों ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की 'धुप्पी को लेकर सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा शांति की अपील करने का आग्रह किया था।

मणिपुर पर मौन हैं। मणिपुर में करीब एक महीने पहले मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'तो एक और 'मन की बात लेकिन 'मणिपुर पर मौन। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए प्रधानमंत्री ने खुद की पीठ थपथपाई। पूरी तरह से मानव निर्मित उस मानवीय आपदा का क्या, जिसका सामना मणिपुर कर रहा है। रमेश ने ट्विटर पर कहा, 'अभी भी उनकी (प्रधानमंत्री) ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर-लेखापरीक्षा योग्य 'पीएम-केयर फंड है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की भी परवाह है, यही असली सवाल है। इससे पहले रविवार को रेडियो पर प्रसारित 'मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो ताकत भारत ने वर्षों से विकसित की है, वह आज मिसाल बन रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर के 10 विपक्षी दलों ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की 'धुप्पी को लेकर सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा शांति की अपील करने का आग्रह किया था।

मणिपुर पर मौन हैं। मणिपुर में करीब एक महीने पहले मेइती और कुकी समुदाय के बीच भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'तो एक और 'मन की बात लेकिन 'मणिपुर पर मौन। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए प्रधानमंत्री ने खुद की पीठ थपथपाई। पूरी तरह से मानव निर्मित उस मानवीय आपदा का क्या, जिसका सामना मणिपुर कर रहा है। रमेश ने ट्विटर पर कहा, 'अभी भी उनकी (प्रधानमंत्री) ओर से शांति की अपील नहीं की गई है। एक गैर-लेखापरीक्षा योग्य 'पीएम-केयर फंड है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की भी परवाह है, यही असली सवाल है। इससे पहले रविवार को रेडियो पर प्रसारित 'मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपदा प्रबंधन की जो ताकत भारत ने वर्षों से विकसित की है, वह आज मिसाल बन रही है। कांग्रेस के नेतृत्व में मणिपुर के 10 विपक्षी दलों ने शनिवार को पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की 'धुप्पी को लेकर सवाल उठाया था और प्रधानमंत्री से मुलाकात का समय देने तथा शांति की अपील करने का आग्रह किया था।



# सम्पादकीय

## मणिपुर में अनवरत हिंसा!

लेखक एक माह से ज्यादा समय से पूर्वोक्त के राज्य मणिपुर में जिस तरह से हिंसा का तांडव चल रहा है वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऐसा लग रहा है कि राज्य में कानून—व्यवस्था तार—तार हो चुकी है। मणिपुर अपनी मनभावन संस्कृति के लिए भारत के मैदानी इलाकों के राज्यों में भी जाना जाता है विशेषकर 'मणिपुरी नर्चर' के लिए। मगर वर्तमान में इस राज्य के दो जातीय समूहों 'कुकी' व 'मैतेई' में जिस तरह का आपसी युद्ध चल रहा है उसकी लम्पटों में सरकारी सुरक्षा सैन्य बल भी झुलस रहे हैं। हद तो यह हो गई है कि प्रशासनिक व कानून—व्यवस्था कायम करने वाले बलों असम राइफल्स से लेकर रैपिड एक्शन फोर्स तक के जवानों पर भी खुल कर हमले हो रहे हैं। मणिपुर ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी इम्फाल तो इसके मैदानी इलाकों में पड़ती है परन्तु इसके पहाड़ी क्षेत्र पड़ोसी देश म्यांमार की सीमा से जाकर लगते हैं। मैदानी क्षेत्र में मैतेई जनजातीय लोगों की अधिकता है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में कुकी जनजाति के लोगों की अधिकता है परन्तु आबादी की दृष्टि से देखा जाये तो मैतेई समाज के लोग बहुसंख्यक कहे जायेंगे, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक हिन्दू धर्म के मानने वाले हैं। कुकी पहाड़ों पर रहने वाले जनजातीय लोग हैं और इनमें ईसाई चर्चों का खासा प्रभाव रहा है। कुकी समुदाय के लोगों को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत अपनी समुदायगत परंपराएं व रीति—रिवाजों को मानने की छूट के साथ ही अधिकृत जनजाति का दर्जा मिलने की वजह से अपने रिहायशी इलाके की भूमि व इसके क्षेत्र के संरक्षण का अधिकार भी संविधान देता है परन्तु पड़ोसी देश म्यांमार में भी इस जाति के कुकी लोग रहते हैं जो भारतीय कुकियों से बहुत मिलते—जुलते हैं और वे प्रायः सीमा पार करके भारतीय इलाकों में भी बसते रहते हैं। इनमें से अधिसंख्य ईसाई हैं। हालांकि मणिपुर में कभी साम्रदायिक भेदभाव का मुद्दा नहीं रहा। अतीत में इस समस्या पर काबू पाने में केन्द्र सरकारों सफल रही और किसी भी प्रकार के सशस्त्र विद्रोह से उन्होंने कुकी लोगों को अलग कर दिया। हालांकि मैतेई समाज के लोगों की कुकी समाज के साथ कभी सीधी रंजिश नहीं रही परन्तु विगत महीने राज्य के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए और सम्बन्धित अनुशंसा केन्द्र सरकार से करनी चाहिए। इससे मणिपुर में कुकी समुदाय के लोगों का गुस्सा चढ़ गया और मैतेई समाज की जवाबी हिंसा पर उतारू हो गया। परिणाम यह हुआ कि पुलिस से लेकर असम सरकारी विभागों में कार्यरत कुकी व मैतेई समाज के लोग एक—दूसरे के खिलाफ खड़े होने लगे। यही वजह है कि जहां कुकी लोगों को मौका मिलता है वे मैतेई समाज के लोगों की हत्या कर देते हैं और मैतेई समाज के लोग ऊपर पहाड़ों पर भेजे जाने वाली सफाई के मार्ग में बाधा खड़ी करते हैं और हत्या करने से भी नहीं चूकते। यहां तक सुरक्षा बलों में तैनात कुकी व मैतेई लोग भी हिंसा के शिकार हो रहे हैं। पिछले एक महीने से यह सिलसिला जारी है और प्रत्येक शांति प्रयास विफल हो रहे हैं। कुकी लोग मैतेई समाज को जनजाति का दर्जा दिये जाने के सख्त खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ऐसा होने से उनके पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत सम्पन्न मैतेई समाज कब्जा कर लेगा और अपने काम—धंधे शुरू कर देगा। जनजाति का दर्जा मिलते ही मैतेई समाज के लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदने व व्यवसाय करने के अधिकार हो जायेंगे। कुकी समाज को यह खतरा बहुत बड़ा लगता है और वे मानते हैं कि ऐसा होने से उनकी विशिष्टता ही समाप्त हो जायेगी। जबकि मैतेई समाज भी मूल रूप से जनजाति समाज ही है हालांकि वह ज्यादा दिवंगत और सम्पन्न माना जाता है। विगत रात्रि जिस तरह से केन्द्र के शिष्ट राज्यमन्त्री राजकुमार रंजन सिंह के इम्फाल स्थित निवास को आग लगा दी गई। इससे एक दिन पहले राज्य के एक कैबिनेट मन्त्री के आवास की भी यही हालत की गई थी। तब ही बाजपा व क्षेत्रीय दल एनपीपी की मिलीजुली सहयोगिता है। यह हालत तब है जब राज्य को संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत केन्द्रीय निगरानी में ले लिया गया है और केन्द्रीय सुरक्षा बलों को पर्याप्त संख्या में तैनात कर दिया गया है। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कुकी व मैतेई संघर्ष के चलते सारे इन्तजायम असफल हो रहे हैं क्योंकि मणिपुर के लोगों के बीच ही आन्तरिक संघर्ष और खून—खराबा चल रहा है।

## कांग्रेस को राज्यों में प्रभारियों की जरूरत

गोरक्ष साहित्य में बदलाव की शुरुआत हो गई है। पहला बदलाव गुजरात में हुआ है, जहां शक्ति सिंह गोहिल को अध्यक्ष बनाया गया है। उनके अलावा वर्षा अमरकावाड़ को मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। पुद्दुचेरी में भी कांग्रेस ने नया अध्यक्ष बनाया है। कहा जा रहा है कि नए अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ही केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी और राज्यों में नए प्रभारी बनाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने शक्ति सिंह गोहिल की जगह गुजरात के ही नेता दीपक तारावारिया को दिल्ली और हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है लेकिन बताया जा रहा है कि यह भी अस्थायी व्यवस्था है। केंद्रीय पदाधिकारियों की नियुक्ति के बाद ही स्थायी रूप से राज्यों का प्रभार बंटेगा। इस बीच कई राज्यों में अलग अलग कार्यकर्ताओं से कांग्रेस को प्रभारियों की जरूरत है। कांग्रेस में एक व्यक्ति, एक पद का सिद्धांत है। इसके तहत दो राज्यों में तत्काल प्रभारी नियुक्त करने की जरूरत है। मिलापलनाडु के कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडुवार और महाराष्ट्र के प्रभारी एकपते पाटिल दोनों कानांकट की नई सरकार में मंत्री बन चुके हैं। उनकी जगह दोनों अहम राज्यों में प्रभारी नियुक्त किया जाना है। इसी तरह पिछले साल गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से हारने के बाद प्रभारी रघु शर्मा ने पद छोड़ने की पेशकश की थी।

ही शुरु हो गई थी, लेकिन जब कभी उनहोंने अपनी व्यक्तिगत पसंद और नफसंदे के हिसाब से नियुक्तियाँ करनी चाहीं तो वह सफल नहीं हो पाए। इसकी वजह थी तत्कालीन न्यायाधीशों का उदात्त चरित्र और अपने-आपके प्रति प्रतिमान-सम्मान का भाव। जब भी किसी न्यायाधीश की वरिष्ठता की अनदेखी कर किसी अन्य न्यायाधीश को आगे बढ़ने की पहल हुई, सभी ने एक स्वर में उसका विरोध किया। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को उच्च न्यायालयों में मामलों, विशेष रूप से आपराधिक अपीलों के लंबित होने पर दुख व्यक्त किया, क्योंकि यह एक हत्या के दोषी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जबकि उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। एनजेडीजी के गत दिवस जारी किए गए आंकड़े के अनुसार, पूरे भारत में जिला और तालुका अदालतों में लंबित कुल 32.9 मिलियन मामलों में से 8.5 फीसदी, या 2.8 मिलियन, 10 से अधिक वर्षों से बने हुए हैं, जो दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है और लंबित मामलों के समेकित आंकड़े प्रदान करता है। 500,000 से अधिक, या जिला और तालुका स्तर पर लंबित मामलों का 1.5%, दो दशक से अधिक पुराने हैं,



रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया। इस युद्ध के जल्दी खत्म होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा एक ही झटके में लड़ाई का निपटारा कर देने के नाम पर अपनी सारी ताकत झोंक देने की गलती रूस नहीं करने वाला। विश्व युद्ध या परमाणु युद्ध का रूप ले लेना इस युद्ध में असम्भव

तो नहीं लेकिन ट्रिगर प्वाइंट पर अंगुली रखने की भूल रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं कर रहे। यद्यपि उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार पहुंचाने की घोषणा कर दी है। रूस-यूक्रेन युद्ध का असर समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। दुनियाभर में अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल चुका है। युद्ध से विश्व दो गुटों में बंट

गया है। तेल, ऊर्जा और खाद्यान्न की आपूर्ति प्रभावित होने से कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कई देशों में खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित अफ्रीकी देश हुए हैं। इन अफ्रीकी देशों में भूखमरी की आशंका बढ़ती जा रही है। पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे अफ्रीकी देशों में घबराहट और

## आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी पर क्या यह निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं



प्रबल हो जाती है। आधार कार्ड के दुषप्रयोग की दूसरी समस्या इसके राजनीतिक प्रतीतिबंध के रूप में उपयोग किए जाने की हो सकती है। राजनीति में सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका होती है विपक्ष की भूमिका उससे अधिक होती है। आधार कार्ड के आंकड़ों के माध्यम से कोई भी सत्ता पक्ष, विपक्ष की इस भूमिका को सीमित करने का प्रयास कर सकता है। आधार कार्ड की अनिवार्यता के साथ विपक्षी राजनेताओं के संवादों को टैप कर रणनीति का पूर्वानुमान लगाना सत्ता पक्ष की मंशा हो सकती है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। पर इसके कई फायदे भी हैं, आधार कार्ड के पैनों का उपयोग अनिवार्यता ने वर्षों से टैक्स की छूट ले रहे फर्जी पैन कार्ड धारकों के हितों में चोट तो की है। इससे सरकार के कर संग्रहण में बढ़ोतरी

होने से योजनाओं के लिए धन आवंटन में  
एवं मौलिक सामाजिक निवेश में वृद्धि  
होगी। आधार कार्ड की अनिवार्यता से  
स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ायी  
जा सकता है क्योंकि इससे सरकार  
के पास वार्षिक सफलता के आंकड़ों  
ही उपलब्ध होंगे जो बेहतर नीति निर्माण  
के लिए सहायक नहीं होगी। गिगत दिनों  
सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भले ही  
निजता का अधिकार मौलिक अधिकार  
हो किंतु सरकार द्वारा जनकल्याण के  
कार्यों के लिए उसका अतिक्रमण किया  
जा सकता है। एक लोकतांत्रिक  
सरकार का प्रथम एवं अंतिम उद्देश्य  
लोक कल्याणकारी रूप में स्वयं को  
स्थापित करना है। यदि लोक कल्याण  
के लिए सरकार व्यक्तियों के आंकड़ों  
का संग्रहण करती है उसे उचित माना  
जाना चाहिए। शायद यह है कि सरकार  
विधि सम्मत प्रत्यक्ष कर दें कि उन

## कब मिलेगा न्याय पता नहीं ?



जबकि 83,141 मामले तीन दशकों से अधिक समय से अनिर्णीत हैं। लंबित मामलों के मामले में जिला अदालतों का प्रदर्शन उच्च न्यायालयों से बेहतर है। देश भर के 25 उच्च न्यायालयों के समक्ष 7 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं। उनमें से, 920,000 से अधिक मामले, या 19.26%, 10 से अधिक वर्षों से और 158,000 (3.3%) 20 से अधिक वर्षों से और 46,754 तीन दशकों या उससे अधिक समय से

लंबित हैं। उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जिला और तालुका अदालतों में 10 वर्ष से अधिक वर्षों से लंबित 2.8 मिलियन मामलों में से 40: और 20 से अधिक वर्षों से पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे 500,000 में से 43: के लिए जिम्मेदार हैं। 30 से अधिक वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर लंबित 85,141 मामलों में से 40: या 34,000 उत्तर प्रदेश में हैं।

अधिक लंबित मामले हैं। उच्च न्यायालय में 10 से अधिक वर्षों से लंबित 920,000 मामलों में से यह 30: या 276,000 है। उच्च न्यायालय में 20 वर्षों से पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे 55 से अधिक मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं। तीन दशक पुराने मामलों की बात करें तो यह प्रतिशत 86 (46,754 में से 40,374) है। इसके पीछे जो मुख्य कारण सामने आए उनका आकलन तारखालिन कानून मंत्री

# युद्ध और अफ्रीकी देश

परेशानी है। युद्ध के चलते यूक्रेन और रूसी अनाज निर्यात में भी काफी कमी आई है। जिस कारण संकट गहराता जा रहा है। दाने-दाने को तरस रहे अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधिमंडल युद्ध को समाप्त करने के तरीकों की तलाश करने यूक्रेन पहुंचा हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति शिरिज़ ममाफोसा और जांबिया, सेनेगल, युगांडा, मित्र और कांगो के वरिष्ठ नेता और अधिकारी शामिल हैं। अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडल के यूक्रेन पहुंचते ही राजधानी कीव में रूसी हवाई हमले का सायरन बजा और विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इससे रूस ने यह सीधा संकेत दे दिया है कि वह युद्ध जल्द खत्म करने का इच्छुक नहीं है। यद्यपि ब्लादिमीर पुतिन ने भी अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक करने पर सहमति व्यक्त की है। अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की सहमति पहले ही दे दी थी और अफ्रीकी प्रतिनिधिमंडल ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में पुतिन से मुलाकात भी कर ली है। अफ्रीकी देशों नेताओं का उद्देश्य युद्ध समाप्त करने के लिए न केवल एक शांति प्रक्रिया शुरू करना है, बल्कि यह भी आंकलन करना है कि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को चटते रूस को उबरक नियात

का भुगतान कैसे कर सकते हैं जिसकी अफ्रीकी देशों को सख्त जरूरत है।

रूस और यूक्रेन की दुनिया के कुल गेहूँ निर्यात में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। ऐसे में अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के चलते जो अफ्रीकी देश विशुद्ध आयात पर आश्रित हैं वे चाहते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म हो। उन्हें न तो गेहूँ मिल रहा है, न उर्वरक और न ही अन्य वस्तुएँ। एक तरफ जलवायु परिवर्तन ने पहले ही वैश्विक औसत कृषि उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कोरोना महामारी ने भी खाद्यान्न उत्पादन पर मार की। महामारी के समाप्त हो जाने के बाद गतिविधियों में धीरे-धीरे जोर पकड़ा तो रूस-यूक्रेन युद्ध ने आपत्तिपूर्ण शृंखला को ही छिन्न-भिन्न करके रख दिया।

अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका के देशों में बाढ़ और सूखे से फसलों को काफी नुकसान पहुँचा। खाद्यान्न संकट मानव जीवन से जुड़ी परिस्थितियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है जिससे सामाजिक अशांति का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, अफ्रीका में खाद्य कीमतों में २०20-22 में औसतन 23.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे अधिक है।

खाद्य सामग्रियों की कीमतों में हो रही लगातार वृद्धि का कई अफ्रीकी देशों पर बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) के अनुसार अफ्रीकी देशों

सालाना 1100 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक अनाज आयात करने के लिए 75 बिलियन डालर से अधिक खर्च करते हैं। 2020 में 15 अफ्रीकी देशों ने रूसी संघ या यूक्रेन से अपने गेहूँ उत्पादों का 60 प्रतिशत से अधिक आयात किया। एएफडीसी के अनुसार रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण अफ्रीका महाद्वीप के देशों में लगभग 30 मिलियन टन अनाज की कमी होने की पूरी सम्भावना है और साथ ही अनाज के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी संभावित है। इस तरह की स्थिति कई देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में उथल-पुथल मचा सकती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता तब तक स्थितियों में सुधार नहीं हो सकता। रूस को लेकर अफ्रीकी देश भी आपस में बंटे हुए हैं। यूक्रेन से रूस की वापसी की मांग करने वाले दो संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर मतदान करने की बात आई थी तो आधे से अधिक अफ्रीकी देशों के वोट यूक्रेन के पक्ष में थे। जबकि दक्षिण अफ्रीका ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था। इसके चलते अमेरिका भी उससे नाराज हो गया था कि उसने तटस्थ रुख क्यों अपनाया? अब देखा जा रहा है कि रूस का अफ्रीकी देशों के प्रति क्या रवैया रहता है। अफ्रीकी नेताओं को अपने हितों की रक्षा भी करनी है। यह भी देखा होगा कि मारको और अफ्रीका के संबंध किस कवट बैठते हैं। मान्यता की रक्षा के लिए युद्ध को समाप्त करने का मार्ग तलाशना ही होगा।—**आदित्य नारायण**

एकत्रित आंकड़ों का दुरुपयोग कि-  
किन्ही भी स्थिति में नहीं किया जाएगा।  
व्यक्ति की निजता एक अखंडनिय अडि-  
कार है, किंतु इसकी निरंतरता के  
लिए सरकार का सहयोग अपनी  
कर्तव्यनिष्ठा का पालन भी आवश्यक  
है। व्यक्ति को चाहिए कि वर्तमान  
डिजिटल युग के खतरों को भांपते  
हुए निजी पहचान को किसी भी अना-  
कृत वेबसाइट अथवा व्यक्ति को देने  
से बचें क्योंकि निजता का वास्तविक  
खतरा उससे है, ना कि सरकार को  
आंकड़ों के संग्रहण से है। आंकड़ों  
की उपलब्धता सरकार के लिए अत्यंत  
आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है।  
किंतु सरकार को यह आवश्यक्यता देना  
होगा कि एकत्रित आंकड़ों का किन्हीं  
भी परिस्थितियों में दुरुपयोग नहीं किया  
जाएगा और व्यक्ति की निजता पर  
किसी तरह की आंच आने की संभावना  
नहीं होगी। आज इंटरनेट में देखे  
रहा है हमारी प्रत्येक गतिविधि पर  
नजर है, कल टीवी पर भी हमें देखेगा  
हमारी सुविधा की जानकारी रखेगा  
इससे यह लाभ होगा कि हमारा जीवन  
सरल हो जाएगा किंतु कीमत होगी  
हमारी निजता की इस पर खतरा ना  
हो तो तभी सुविधाएं मानवीय पहलुओं  
को सहायता करना ही है। आज के  
डिजिटल युग में हमें किसी किसी भी  
साइट अथवा किसी भी चैनल को  
अपना आधार कार्ड नंबर उपरने  
बताना चाहिए इससे साइबर अपराध  
को बढ़ोतरी मिलती है एवं धन हानि  
की संभावना ज्यादा होने  
लगेगी।

# आज का

**मेघ :-** आज का दिन शुभ और फलदायी होगा। महत्त्वपूर्ण निर्णय न लेने की सलाह है। यात्रा के योग्य हैं। लेखनकार्य के लिए अच्छा दिन है। महिला के साथ विवाद में न उतरें।

**वृषभ :-** मन को स्थिर रखने की सलाह गणेशजी देते हैं, क्योंकि अनिर्णय की मनोशक्ति से अवसर गवां सकते हैं। प्रवास का आयोजन टाल दें। नए कार्य प्रारंभ न करें।

**मिथुन :-** लक्ष्मीजी की कृपा से दिन लाभदायी होगा। उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र व अपनों के साथ से दिन आनंददायी होगा। धन अधिक व्यय न करें।

**कर्क :-** कोई भी महत्त्वपूर्ण निर्णय न लें। संबंधियों से मनमुटाव हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। स्वास्थ्य ध्यान रखें। मानहानि एवं धनहानि से बचें।

**सिंह :-** आज का दिन लाभदायी है। मित्रों से लाभ और पर्यटन की संभावना है। हाथ आया अवसर जा सकता है, इसलिए निर्णय टाल दें। व्यापार एवं आर्थिक लाभ के योग्य हैं।

**कन्या :-** आज दिन शुभ है। नए कार्य संपन्न होंगे। व्यापारी व नौकरिपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है। व्यापार में लाभ व नौकरी में पदोन्नति के योग्य हैं। पिता से लाभ होगा।

# राशिफल

**तुला :-** व्यावसाय में लाभ की संभावना है ऐसा गणेशजी कहते हैं। नौकरी में व्यापार में सहकर्मियों से सहयोग नहीं मिलेगा। लंबी यात्रा का आयोजन हो सकता है। अस्वस्थ रहेंगे।

**पृथिविक :-** आज शांति व सावधानीपूर्वक रूप से रहने की गणेशजी की सलाह है। नए कार्यों में असफलता के योग हैं। क्रोध पर संयम रखें। सरकार विरोधी प्रवृत्तियों से दूर रहें।

**धनु :-** आज का दिन आनंदपूर्वक बीतेगा। सहवास का आनंद मिलेगा। प्रवास, पर्यटन होगा। लेखनकार्य के दिन अनुकूल हैं। साझेदारी से लाभ होगा।

**मकर :-** व्यापार में विकास के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा। धन के लेनदेन में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा।

**कुंभ :-** आप की वाणी व विचारों में शोध परिवर्तन होगा। बौद्धिक चर्चा में शामिल होंगे। आकस्मिक खर्च की आशंका है। पाचन न होने जैसी बीमारियों से परेशान होंगे।

**मीन :-** गणेशजी कहते हैं कि आप में उत्साह व स्फूर्ति की कमी होगी। परिजनों के साथ विवाद न करें। अस्वस्थ महसूस करेंगे। नौकरी में चिंता रहेगी। धन व कीर्ति की हानि न हो यात्रा रहें।

भाजपा केवल उच्च न्यायालयों और उच्च न्यायालय न्यायालय में लंबित मुकदमों को ही देखें तो उनकी संख्या लाखों में दिखती है। अगर जिला और अधीनस्थ अदालतों में भी लंबित मुकदमों की गिनती कर लें तो यह संख्या करोड़ों में पहुँच जाती है। यह बहुत सुखद स्थिति नहीं है। एक दो नहीं सैकड़ हज़ारों ऐसे मामले हैं जिसमें न्यायिक की आस में फरियादियों की मात्रा घटी गई लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। लोगों को समय नष्ट न मिल पाया न मिल पा रही भारतीय न्याय एवं गणतंत्र की एक बड़ी शक्ति है। संविधान सभा में न्यायाधीशों को सर्वोच्च सम्मान प्रेरित स्वतंत्रता देते हुए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य धार्वज, भीमराव आंबेडकर अदि ने जो उद्गार व्यक्त किए थे उनका पालना यही था कि हमारे न्यायाधीश न केवल उच्च कोटि वाले, अपरन सर्वोत्तम बौद्धिक क्षमता और न्याय प्रक्रिया में तटस्थ और किसी भी पक्ष में उलझने वाले होंगे। वे न्याय देने में न केवल शीघ्रता, बल्कि निष्पक्षता का परिचय भी देंगे। वे भारतीय न्यायिक की उस गरिमा को कायम रखेंगे जिसमें न्यायाधीश को ईश्वर का अंश माना गया है। हालांकि न्यायाधीशों की ओर से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिशें पड़ित नेहरू के समय से

ही शुरु हो गई थी, लेकिन जब कभी उनहोंने अपनी व्यक्तिगत पसंद और नफसंदे के हिसाब से नियुक्तियाँ करनी चाहीं तो वह सफल नहीं हो पाए। इसकी वजह थी तत्कालीन न्यायाधीशों का उदात्त चरित्र और अपने-आपके प्रति प्रतिमान-सम्मान का भाव। जब भी किसी न्यायाधीश की वरिष्ठता की अनदेखी कर किसी अन्य न्यायाधीश को आगे बढ़ने की पहल हुई, सभी ने एक स्वर में उसका विरोध किया। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को उच्च न्यायालयों में मामलों, विशेष रूप से अपराधिक अपीलों के लंबित होने पर दुख व्यक्त किया, क्योंकि यह एक हत्या के दोषी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जबकि उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। एनजेडीजी के गत दिवस जारी किए गए आंकड़े के अनुसार, पूरे भारत में जिला और तालुका अदालतों में लंबित कुल 32.9 मिलियन मामलों में से 8.5 फीसदी, या 2.8 मिलियन, 10 से अधिक वर्षों से बने हुए हैं, जो दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है और लंबित मामलों के समेकित आंकड़े प्रदान करता है। 500,000 से अधिक, या जिला और तालुका स्तर पर लंबित मामलों का 1.5%, दो दशक से अधिक पुराने हैं,



जबकि 85,141 मामले तीन दशकों से अधिक समय से अनिर्णीत हैं। लंबित मामलों के मामले में जिला अदालतों का प्रदर्शन उच्च न्यायालयों से बेहतर है। देश भर के 25 उच्च न्यायालयों के समक्ष 4.7 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं। उनमें से, 920,000 से अधिक मामले, या 19.26%, 10 से अधिक वर्षों से और 158,000 (3.3%) 20 से अधिक वर्षों से और 46,754 तीन दशकों या उससे अधिक समय से



लंबित हैं। उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, जिला और तालुका अदालतों में 10 से अधिक वर्षों से लंबित 2.8 मिलियन मामलों में से 40: और 20 से अधिक वर्षों से पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे 500,000 में से 43: के लिए जिम्मेदार है। 30 से अधिक वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर लंबित 85,141 मामलों में से 40: या 34,000 उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों में सबसे



अधिक लंबित मामले हैं। उच्च न्यायालयों में 10 से अधिक वर्षों से लंबित 920,000 मामलों में से यह 30: या 276000 है। उच्च न्यायालयों में 20 वर्षों से पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे 55: से अधिक मामले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित हैं। तीन दशक पुराने मामलों की बात करें तो यह प्रतिशत 86 (46,754) में से 40,374) है। इसके पीछे जो मुख्य कारण सामने आए उनका आकलन तत्कालिन कानून मंत्री

किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बता चुके हैं उनके अनुसार देश के अंदर हाईकोर्ट के जज के लगभग 30 प्रतिशत पद खाली हैं, उच्च न्यायालय में 1114 जजों की स्वीकृत संख्या है और वर्तमान में 780 पद भरे हुए हैं जबकि 334 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालयों में 334 पदों के लिए हाईकोर्ट कॉलेजियम की की 118 सिफारिशें चरणों में हैं, जबकि सरकार को अभी तक 216 वेकेंसी के लिए सिफारिशें नहीं मिली हैं। लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि 10 मार्व को सुप्रीम कोर्ट में कोई पद खाली नहीं था. 25 उच्च न्यायालयों में 1,114 न्यायाधीशों की स्वीकृत हैं, जिसमें 780 न्यायाधीश काम कर रहे थे जिसमें 334 की कम हैं। उन्होंने कहा था कि वर्तमान में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित कुल 118 प्रस्ताव हैं। वैसे तो नए न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के इस कथन से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि लंबित मुकदमों का निपटारा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस तरह की बातें न जाने कब से हो रही हैं। लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। दशकों से इस तरह के आश्वासनों के बाद भी लंबित मुकदमों का बोझ कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार इस समय देश भर के अदालतों में चार करोड़ से अधिक

मुकदमे लंबित हैं। एक लाख से अधिक मामले ऐसे हैं, जो तीन दशक से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। ये मामले सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक में हैं। देश में लंबित मुकदमों के निस्तारण की कोई ठोस व्यवस्था बन पा रही है और न ही वर्तमान मामलों के तेजी से निष्पादन का कोई तंत्र विकसित किया जा पा रहा है। इसी कारण यह उक्ति चरितार्थ हो रही है कि न्याय में देरी अन्याय है। इस अन्याय से सभी परिचित हैं, लेकिन त्वरित न्याय के लिए कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है। निराशाजनक यह है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोग न्यायिक तंत्र में सुधार की बातें करके कर्तव्य की इतिश्री करते रह जाते हैं। आखिर लंबित मुकदमों को लेकर जल्ती जाने वाली उस चिंता का क्या मूल्या—महत्व, जिसका कोई समाधान होता हुआ न दिखे ? अब जब नए कानून मंत्री यह कर रहे हैं कि लंबित मामलों का निपटारा सरकार की पहली प्राथमिकता है, तब उन्हीं इस तथ्य को ओझल नहीं करना चाहिए कि सबसे बड़ी मुकदमेबाज तो खुद सरकार हैं। क्या इससे बड़ी विवर्धना और ही हो सकती है कि सरकारों अपने ही लोगों से अदालतों में मुकाबला करें ? यह ठीक है कि कानून मंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के जो 328

पद रिक्त हैं, उन्हें भरने के लिए सरकार सक्रिय है, लेकिन प्रश्न यह है कि इतने अधिक पद समय रहते क्यों नहीं भरे जाते ? जब उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने का काम तेजी से नहीं हो पाता तो फिर कोई भी यह समझ सकता है कि निचली अदालतों में रिक्त पदों को भरने में कितनी देरी होती होगी ? समस्या यह है कि यदि रिक्त पदों को भर दिया जाए तो भी बात बनने वाली नहीं, क्योंकि उन कारणों का निवारण नहीं किया जा पा रहा है, जिनके चलते तारीख पर तारीख का सिलसिला कमर रहता है। चूँकि मामलों का निपटारा समय पर नहीं होता, इसलिए आम आदमी समस्याओं से घिरेन के बाद भी अदालतों का रुख करने से बचता है। यह चिंताजनक है कि न्यायिक तंत्र की शिथिलता के चलते लोग अदालतों का दरवाजा खटखटाने से बचें। यह स्थिति लोगों को न्याय से वंचित करने, देश की प्रगति को थामने और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। चिन्ताजनक बात यह कि देश में अल्पस्थ रूप से ताकतवर, राजनैतिक हस्तियों एवं अर्थतंत्र ने भी देश की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कमजोर करने में न्याय कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में देश में अमजबूत मानस को न्याय कब मिलेगा इसकी कोई गारन्टी नहीं है।—**प्रेमराज शर्मा**







## जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीएम किसान सम्मान निधि, कोर्ट केस अवमानना वाद एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

**प्रयाग दर्पण संवाददाता मऊ।** जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय स्थित सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वरासत अभियान, कोर्ट केस एवं अवमानना वाद, फैमिली आईडी की प्रगति तथा अवैध खनन एवं नियम विरुद्ध लाउडस्पीकर के खिलाफ की जा रही कार्यवाहियों सहित तहसील स्तरीय कई अन्य योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नेडा द्वारा जनपद में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली।इस दौरान वित्तीय वर्ष 2022–23 की कई योजनाएं अभी तक पूर्ण न होने एवं कई अन्य योजनाओं पर अभी तक कार्य प्रारंभ ना होने पर जिलािहिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए भीओ नेडा एवं वरिष्ठ लिपिक का वेतन बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला विकास अधिकारी को नेडा द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेंडू टेंडर जारी करने, सामानों की आपूर्ति एवं कार्यों की प्रगति की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। फैमिली आईडी के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उप जिला अधिकारियों को खंड विकास अिहिकारियों के साथ बैठक कर इसमें तेजी

## संक्षिप्त खबरे

**भाजपाइयों ने सुनी प्रधानमंत्री जी की मन की बात**

**प्रयागराज।** भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज महानगर के द्वारा कीडंगंज कार्यालय में महापौर एवं भाजपा महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रसारित मन की बात के कार्यक्रम से समाज को राष्ट्र के प्रति कार्य करने की एक नई राह मिली है और नई पीढ़ियों के लिए समाज और राष्ट्र के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रेरक सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के द्वारा भारतीय संस्कृ ति और सभ्यता की हमारी जो पहचान है जन–जन तक पहुंचा रहे है और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए समाज के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। मीडिया प्रमारी राजेश केसरवानी ने बताया कि प्रयागराज महानगर के द्वारा 1297 बूथों पर मन की बात का आयोजन किया गया।इस अवसर पर प्रमुख रूप से अवधेश चंद्र गुप्ता कमलेश कुमार, कुंज बिहारी मिश्रा, देवेश सिंह, वरुण केसरवानी, राजेश केसरवानी, मनीष केसरवानी, सुनील केसरवानी सोनू, विवेक अग्रवाल, राजू पाठक, गिरगेश मिश्रा, प्रदीप यादव, विजय श्रीवास्तव एवं सभी बूथ अध्यक्ष गण अपने–अपने बूथों पर मन की बात को सुना।

**भगवान जगन्नाथ जी की कथा श्रवण करने से**

**सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है: आचार्य मनोज**

**प्रयागराज।** श्री जगन्नाथ जी महोत्सव समिति ट्रस्ट प्रयागराज के द्वारा और भवन में चल रही भगवान जगन्नाथ जी की कथा के चतुर्थ दिवस पर आचार्य मनोज जी ने कथा का रसपान कराते हुए कहा कि चौर मास में आने वाले चारों सोमवार को तिसुआ सोमवार कहा जाता है। इस सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड से, दूसरे सोमवार को गुड और धनिया से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से तथा चौथे सोमवार को कच्चा पक्का, हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि सुदामा ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामाजी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीढ़ियों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए मन्तव मांगेंगे। बताया जाता है सुदामा की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर एक ब्राह्मण के भेष में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बड़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीढ़ियों के दुख दूर करने की प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बैत देकर कहा कि जिसे यह बैत मांगेगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तब से चौर मास शुक्ल पक्ष शुरु होने पर श्रद्धालु भक्तिपूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन–अर्चन करते हैं और उनके बैत खाल अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। कार्यक्रम का संचालन बसंत लाल आजाद ने किया और काढ़ा प्रसाद का भोग लगाया।इस अवसर पर अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद गुप्ता, जय राम गुप्ता ,दाऊ दयाल गुप्ता , गगन दास गुप्ता, राजेश केसरवानी, त्रिलोकी केसरवानी, गीता गुप्ता, हैप्पी कसेरा आदि ने भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारी।

**फुटपाथ व्यापारियों का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न**

**प्रयागराज।** फुटपाथ व्यापारी एकता समिति का शपथ ग्रहण समारोह शिविल लाइन स्थित बी एस एन एल आफिस के पास सम्पन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी का व्यापारी एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता व संस्था के मुख्य संरक्षक ने स्वागत किया। फुटपाथ व्यापारी एकता समिति के अध्यक्ष के रूप में विकास अग्रहरि के साथ विमल गुप्ता महामन्त्री, श्रीमती लीलावती पाण्डेय व कमलेश कुमार उपाध्यक्ष, रुद्रेश यादव कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने देश समाज राष्ट्र व व्यापारी हित में काम करने की शपथ ली।इस अवसर पर मुख्य अतिथि व विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी ने कहा कि फुटपाथ पर छोटी पूंजी से व्यापार करने वाले व्यापारी अनेकानेक संकटों से जूझते हुए समाज की सेवा करते हैं इसलिए मैं इनके हितों के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ।

समारोह में फुटपाथ व्यापारी एकता समिति प्रयागराज मुख्य संरक्षक विजय गुप्ता ने कहा कि समाज में होने वाले धार्मिक व सामाजिक सेवा हेतु फुटपाथ पर बैठा व्यापारी आगे आकर तन मन धन से सहयोग करता है।कार्यक्रम का संचालन अवधेश निषाद ने किया। समारोह में मुख्य रूप से पार्षद आशीष द्विवेदी, मनीष गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, सीतादेवी, रानी केसरवानी, कलावती गुप्ता, सारिका शर्मा, इषितखार अंसारी गणेश गुप्ता आदि ने सम्बोधित किया।

**महापौर ने किया नए रिबोर नलकूपों का उद्घाटन**

**प्रयागराज।** महापौर गणेश केसरवानी ने विजयपुर कोठी मुडीगंज जोन 2, मोहितसमर्गज सक्की मंडी के पास , दशा सुमेर मंदिर के पास वारागंज जोन 4, एवं आजाद नगर रसूलाबाद जोन 3 के नए रिबन नलकूपों का लोकार्पण किया।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने हर घर नल और हर नल में जल के लिए जो संकल्प लिए हैं उसे संकल्प को सिद्धि तक ले जाना और जनता जनार्दन को स्वच्छ पानी घर–घर तक पहुंचाने का काम ट्रिपल इंजन की सरकार कर रही है। इस अवसर पर वरुण केसरवानी, राजेश केसरवानी, पार्षद नीरज गुप्ता, पार्षद कुसुम लता गुप्ता, पार्षद सुप्रिया दास, पार्षद मीनू तिवारी, अजय अग्रहरि, भरत निषाद, विजय अग्रवाल, मनीष केसरवानी, राजन शुक्ला, सुनील केसरवानी, सोनू कन्हैया लाल गुप्ता, नीरज केसरवानी हरीश मिश्रा एवं स्थानीय जनता उपस्थित रही।

## एमआईसी में 30 लोगों ने किया रक्तदान

निर्देश दिए। कोर्ट केस एवं अवमानना वाद की समीक्षा के दौरान नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि किसी भी मामले में अवमानना वाद की स्थिति अभी नहीं है। अवैध खनन, नियम विरुद्ध लाउडस्पीकरछ्डीजे के खिलाफ अब तक की गई कार्यवाहीयों की भी जानकारी लेते हुए जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। अवैध खनन के खिलाफ की जा रही कार्रवाईयों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने बिना वजह आम लोगों को परेशान न करने तथा अवैध खनन से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा। आइजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण आख्या न लगने पर डिफाक्टर हो जाने की स्थिति में उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण आख्या लगाने के निर्देश करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने डॉ आंबेडकर उत्सव योजना, सॉलिड वेस्ट प्लांट निर्माण एवं गो आश्रय स्थलों कारियों को खतौनी का नियमित निरीक्षण कर गुणवत्ता पूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण करने को कहा। मोटर दुर्घटना क्लेम, पारिवारिक न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में से प्राप्त आरसी की वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधितो के खाते सीज करने एवं उनकी अचल

## रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर दुर्लभ अभिलेख एवं चित्र प्रदर्शनी का आयोजन

**प्रयाग दर्पण संवाददाता प्रयागराज।** आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के अवसर दुर्लभ अभिलेख एवं चित्र प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन आज क्षेत्रीय अभिलेखारण प्रयागराज में किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉ सालेहा रशीद विभागाध्यक्ष अरबी फारसी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज द्वारा किया गया गया।प्रस्तुत प्रदर्शनी में प्रमुख रूप से रानी लक्ष्मीबाई द्वारा हस्ताक्षर युक्त पत्र, दीवान लक्ष्मणराव सलाहकार रानी लक्ष्मीबाई को कालापानी की सजा, रानी लक्ष्मीबाई की सम्पत्ति जब्ती अभिलेख, रानी के बनारस स्थित भवनों की सूची, रानी की मृत्यु संबंधी टेलीग्राफ, रानी के सहयोगियों महीप सिंह, दीवान लक्ष्मण राव, भोले अहीर, लाला दुबे को दी गई फांसी तथा कलापानी की सजा संबंधित अभिलेखों को प्रदर्शित

**पुलिस गिरफ्त में गांजा कारोबारी**

**चित्रकूट।** पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम कसे जारी अभियान में एससपी चक्रपाणि त्रिपाठी, सीओ राजापुर शीतला प्रसाद पाण्डेय की देखरेख में प्रमारी निरीक्षक पहाडी नागेन्द्र कुमार नागर की अनुवाई में पुलिस ने तीन अन्तर्राष्ट्रीय गांजा तस्करी को 15 किलो गांजा समेत गिरफ्तार किया।

रविवार को पहाड़ी थाने के वरिष्ठ दरोगा राहुल पाण्डेय की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सिंघनिया तालाब अरसे के पास से सुखचन्द्र भन्ना पुत्र नरतन भन्ना निवासी कुमुली थाना रायधर जिला नवरंग उड़ीसा को छह किलो गांजा, कार्तिक बड़नायक पुत्र नरसिंह निवासी पिपलपुट थाना मांझाकुण्ड जिला कोरापुट उड़ीसा के कब्जे से पांच किलो गांजा व प्रिति गुप्ता पत्नी भक्ता गुप्ता निवासी आदिवासी कलौनी थाना रायधर जिला नवरंग उड़ीसा को चार किलो गांजा समेत गिरफ्तार किया। पूंछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे उड़ीसा से गांजा तस्करी करके लाते है।

### जैविक कृषि हमारी परंपरागत कृषि: डॉ. स्वरूप

**प्रयाग दर्पण संवाददाता प्रयागराज।** सोसायटी आफ बायोलॉजिकल साईंसेज एंड फूड डेवलपमेंट , प्रयागराज में दूसरे दिन का जैविक खेती नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी वक्ताओं एवं प्रतिभागियों का स्वागत डॉक्टर हेमलता पंत ने किया। इस कार्यक्रम में प्रथम वक्ता डॉ डी स्वरूप पशु वैज्ञानिक  मैनपुरी रहे। डॉ डी स्वरूप ने रोल ऑफ लाइवस्फेयर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अपना व्याख्यान दिया। डॉक्टर स्वरूप ने बताया कि जैविक कृषि हमारी परंपरागत कृषि है। हमारे पशु हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यदि हमें जैविक खेती करनी है तो हमारे पास पशुधन होना ही चाहिए। पशुधन से मिलने वाला गोबर, मूत्र, बकरी, भेड़ के मल मूत्र एवम् इसकी सिंघ और खुर में नाइट्रोजन मिलता हैं।

अतः हमें पशुधन की महत्ता को समझना होगा तथा जागरूक होना होगा।गाय के गोबर में बहुत अधिक लाभदायक जीवाणु मिलते हैं जो मृदा के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। सरकार की एक योजना के अंतर्गत एक आधारा कार्ड पर चार देशी गाय मिल जाएगी। अतः इनसे दूध, दही, मट्ठा, गोमूत्र सब प्राप्त कर सकते हैं। जिससे जैविक

एमआईसी में 30 लोगों

ने किया रक्तदान

**प्रयागराज।** रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद मिडटाउन और इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज (एमआईसी) में किया गया।

कॉलेज के शारिरिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अकील अब्बास रिजवी के अनुसार शिविर में 30 लोगों ने स्‍वैक्षिक रक्तदान किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर गणेश केसरवानी ने रक्तदान करने आये लोगों का उत्साहक नि करते हुए धन्यवाद दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए गर्ल्स टॉयलेट उद्घाटन भी किया।

रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद मिडटाउन के अध्यक्ष सौरभ पुरी और इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अरूप बनर्जी, एमआईसी के प्रबंढ िक फरहान उल्ला, प्रधानाचार्य ख्वाजा तारिक अहमद ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया।

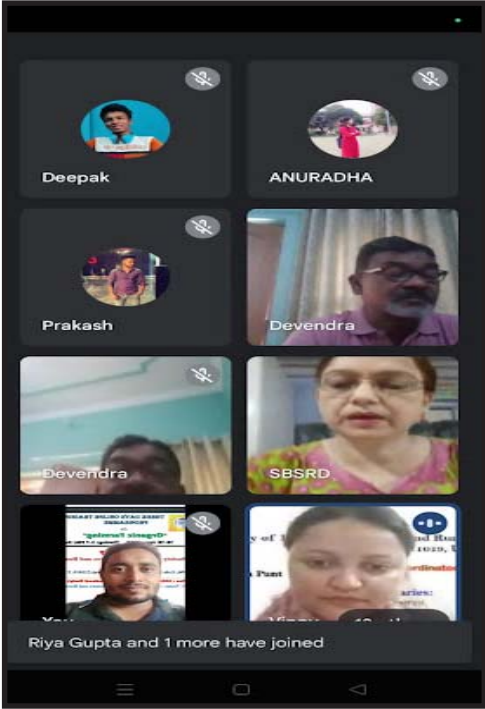
शिविर में उप प्रधानाचार्य अब्दुर रहमान, मो. जावेद, निसार अहमद, इबादुर्रहमान, शाद सऊद के अलावा संस्था रक्त संकल्प व रॉबिन हुड आर्मी ने विशेष सहयोग दिया।

### क्षत-विक्षत अवस्था में मिला 80 वर्षीय वृद्ध का शव

**घोसी, मऊ।** घोसी कोतवाली क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग के हरबंशपुर निवासी 80 वर्षीय तिरछू निषाद का शव गौरीडीह से पकड़ी बुजुर्ग को जाने वाले चक मार्ग पर उनके गांव से कुछ दूरी पर रविवार की सुबह लगभग 10 बजे पाया गया। वह बुधवार की सुबह घर से घोसी आए थे। घोसी से पैदल ही हाथ में लाठी लिए घर जा रहे थे। अनुमान लगाया जाता है कि कड़ी ६ एप के चलते चक्कर खाकर गांव के समीप चकमार्ग के किनारे गिर गए। उनके पुर्‍वों ने मुख्य मार्ग पर तलाश किया पर पता न चला। रविवार की सुबह सिवान में जानवर चरा रहे ग्रामीणों ने क्षत–विक्षत अवस्था में उनका शव देखकर शोर मचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तलाशी लिया। उनकी जेब से 1840 रुपये मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है।

**करेली में बिजली की रोस्टिंग से कैसर, हार्ट तथा किडनी के रोगी परेशान**

**प्रयागराज।** एक तरफ जहां प्रचंड गर्मी से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वहीं करेली से जुड़े आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों में धुआंधार बिजली कटौती हो रही है। रोस्टिंग से बुजुर्गों,महिलाओं, बच्चों और गंभीर बीमारी से ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे मरीजों का जीना मुहाल हो गया है। पिछले एक हफ्ते से हालात यह हो गए हैं कि अब तो रात को भी रोस्टिंग हो रही है। जिसके चलते कैसर, हार्ट, किडनी और अन्य गंभीर रोगियों का जीना दुश्‍वार हो गया है। करेली के करामत चौकी, आजाद नगर, रहमत नगर, शम्स नगर, मदापीपुर, ए ब्लॉक, नया रसूलपुर, 12 मार्केट आदि मोहल्लों के निवासियों परवेज, शाहिद, विनोद अजय, राजीव, अशफाक, मुन्ना, लालजी, राशिद, ग्यास, अफसर, सौभ्र, राकेश, पप्पू, शिवम, बबलू, मिनहाज, अफसरजी, गुड्डिया, सीमा, नं राज, सुनीता, पूजा, अंसार, कादिर, अवसार आदि लोगों ने बताया कि पिछले एक हफ्ते से लाइट का बुरा हाल है। 24 घंटे में कई घंटे लाइट कट रही है। रोस्टिंग के बाद एक घंटे बिजली रहती है तो एक से दो घंटे बिजली गुल रहती है। अब तो सुबह से रात तक रोस्टिंग हो रही है। झुलसा देने वाली गर्मी से जनता परेशान हो गई है। जिसके चलते किसी के पिता, किसी की माता, बहन , पत्नी, भाभी, किसी के बाबा जो कैसर, हार्ट, किडनी गंभीर रोगी हैं। उनका जीना दुश्‍वार हो गया है।बिजली कटौती के चलते पानी भी नहीं मिल रहा है। हालात यह हो गए हैं लोगों को पानी भी खरीदकर पीना पड़ रहा है। जनता का यह भी आरोप है कि पावर हाउस के अधिकारी व कर्मचारी फोन नहीं उठाते। अगर फोन उठाते भी हैं तो लाइन लास का रोना रोकर, धमकी देते हुए फोन काट देते हैं। जबकि इसके जिम्मेदार वे लोग खुद ही हैं और कुछ की गलती की सजा सब को क्यों? करेली क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में बिजली की रोस्टिंग से हाहाकार मचा हुआ है। क्षेत्रवासियों का यह भी कहना है कि एक ओर जहां मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और अपर मुख्य सचिव तथा पावर कारपोरेशन के चेयरमैन का तत्काल बिजली व्यवस्था में सुधार लाने का आदेश है।



खाद को बढ़ावा मिलेगा। गोबर का प्रयोग वर्मी कंपोस्ट, नाडेप, बायोडायनेमिक खाद में भी करते हैं। इस प्रशिक्षण के दूसरे वक्ता डॉ डाखम जेम्स सिंह शूआदस ने अपने वक्तव्य में बताया कि जैविक

अनुराधा यादव, कुमारी निधि गुप्ता सहित 50 प्रतिभागी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विनी ज्ञान एवं ६ पन्‍याद ज्ञापन डॉ अमित कुमार मौर्य ने किया।

## योग प्रोटोकॉल अभ्यासक्रम का आयोजन

**प्रयाग दर्पण संवाददाता**

**प्रायागराज।**राजर्षि टण्डन महिला महाविद्यालय,( संघटक इलाहाबाद विश्वविद्यालय), प्रयागराज और महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के संयुक्त तत्त्वावधान में योग सप्ताह के अन्तर्गत महाविद्यालय परिसर में प्योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया गया। हमारा देश, वर्ष 2023 को 9वें अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस  के रूप में मनाने की तैयारी में है। अतिशय महत्त्वपूर्ण इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में आज महाविद्यालय परिसर में  योग प्रोटोकॉल अभ्यासक्रम आयोजित कराया गया।

कार्यक्रम का प्रारम्भ करते हुए प्राचार्या प्रोफेसर रंजना त्रिपाठी ने छात्राओं का उत्साह वर्धन किया तथा योग के महत्त्व को बताते हुए अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करने को कहा। जिससे छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास भली भांति हो सके। योग प्रशिक्षक डॉ प्रशान्त तिवारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जसरा, प्रयागराज  ने  नवम् अन्तर्राष्ट्रीय योग प्रोटोकॉल के उपलक्ष्य में शिविरार्थी शिक्षक, शिक्षिकाओं, कर्मचारियों और स्वयं

आत्मिक स्वास्थ्य का संवर्धन करता है, इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर प्राचार्या प्रो रंजना त्रिपाठी, कार्यक्रम अधिकारी डॉ कौमुदी श्रीवास्तव, शिक्षिका डॉ शमैनाज बानो तथा शिक्षणेतर कर्मचारी पूजा अग्रवाल के साथ साथ लगभग 40 स्वयं सेविकाओं ने भाग लिया।

## घर में मिली रिटायर्ड रेलवे अफसर की लाश

**प्रायागराज।** धूमनगंज थाना क्षेत्र में रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी की लाश उनके घर में मिली। दुर्गांध उठने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वह इन दिनों अकेले रह रहे थे। उनकी लाश 48 घंटे से ज्यादा पुरानी है। पुलिस ने छानबीन के बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया।प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे में अधिकारी के पद से रिटायर्ड शिवबचन शर्मा तकरीबन 75 वर्ष के थे। धूमनगंज थाना क्षेत्र के इरबो कालोनी, संगम बिहार, झलवा में मकान बनाकर परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी मिथलेश शर्मा अपनी बेटी सुधा शर्मा के पास लखनऊ गई हुई थीं। वह घर पर अकेले थे। आज शिवबचन के घर से पड़ोसियों ने दुर्गंध महसूस की तो पुलिस को खबर दी।पुलिस मौके पर पहुंची तो उनका दरवाजा अंदर से बंद था।

बाहर दो दिन पुराना न्यूज पेपर पड़ा हुआ था। उसके साले डॉ. एमके शर्मा को बुलाया। अंदर दरवाजा खोलकर जब सब लोग अंदर पहुंचे तो फर्श पर रामबचन सिंह की लाश पड़ी हुई थी। लाश पुरानी होने की वजह से दुर्गंध उठने लगी थी। किचेन में रोटी रखी हुई थी।छानबीन के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। उनकी बेटी सुधा, पत्नी मिथिलेश शर्मा भी लखनऊ से आ गए हैं। ईस्पेक्टर धूमनगंज राजेश कुमार मौर्या ने बताया कि शिवबचन शर्मा कई रोगों से ग्रसित थे। आशंका है कि उनकी मौत बीमारी से हुई होगी, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, कुछ नहीं कहा जा सकता।

## प्रयागराज में अमृत सरोवरों में होगा 175 करोड़ लीटर वर्षा जल का संचय

**अमृत सरोवरों में जल संरक्षण में प्रयागराज प्रदेश में अव्वल**

**प्रयागराज।**  यूपी में गांवों में जल

संरक्षण एवं जल संचय पर केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार नेकटेश्वर क्षेत्रफल में इन सरोवरों का निर्माण किया गया है। इन सरोवरों में अब पौने दो अरब लीटर वर्षा का जल संचय किया जाएगा। इस तरह अमृत सरोवरों में वर्षा जल संचयन के विषय में प्रयागराज प्रदेश में अव्वल स्थान पर पहुंचे हैं। संगम नगरी प्रयागराज से इसे लेकर उत्साहित करने वाले परिणाम सामने आये हैं।

संगम नगरी प्रयागराज वर्षा जल संचय को लेकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। अमृत सरोवरों के निर्माण और उनके संरक्षण के विधिवत प्रयास कर रही प्रदेश की योगी सरकार के प्रयास से प्रयागराज जल संरक्षण एवं जल संचयन में प्रदेश में अव्वल स्थान हासिल करने जा रहा है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार

**एसटीएफ ने पकड़ा साढ़े नौ लाख का गांजा**

**प्रयागराज।** एसटीएफ की प्रयागराज प्कडे ने वाराणसी कानपुर हाईवे पर उपरदहा गांव के सामने एक दुकान के पास से दो ईट्टरस्टेड गांजा तस्करी को गिरफ्तार किया है। जिनकी कार में स्पेशल कैविटी बनाकर छिपाए गए 37.600 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। जिसकी अनुमानित कीमत करीब 09. 50 लाख रुपए आंकी गई है। एसटीएफ टीम ने पूछताछ के बाद बताया है कि पकड़े गए दोनों तस्कर काफी दिनों से इस धंधे में लिप्त थे। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेन्डू सिंह ने बताया कि प्रयागराज फील्ड इकाई की टीम को सूचना मिल रही थी कि इन दिनों कानपुर – वाराणसी हाईवे के रास्ते से गांजे की तस्करी की जा रही है। यह गांजा उड़ीसा से मंगा कर प्रयागराज व आसपास के जिलों में हट्टाया जा रहा है। सटीक मुखबिरी पर 17 जून की रात में वाराणसी – कानपुर हाईवे पर समीर गुप्ता की दुकान के सामने उपरदहा गांव के समीप एक संदिग्ध कार को रोका गया।फोर्ड फिएस्टा कार मध्य प्रदेश के रास्ते प्रयागराज की ओर आ रही थी। एसटीएफ टीम ने घेराबंदी करके कार को रोका और तलाशी ली। प्रथम दृष्टया तो उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जब कार के अंदर बनाई गई स्पेशल कैविटी को चेक किया तो उसमें 37.600 किलोग्राम गांजा पैकेट में पैक करके रखा हुआ मिला। जिसे एसटीएफ ने जल्त कर लिया।हिरासत में लिए गए तस्करों में सतीश सिंह पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह निवासी फेसुरा, सैयदपुरा, चंदौली और मिनीकेतन नायक पुत्र धनूयां नायक निवासी मुंडरा, गुडा, मंगलपुर, जयपटना, कालाहांडी, उड़ीसा जो वहा झाइवर था, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि वह लोग पुराने वाहन खरीद कर उसमें स्पेशल कैविटी रूपी एक बॉक्स बनवाते हैं, ताकि वह पकड़े न जा सके। वह लोग उड़ीसा से मिडू नामक व्यक्ति से गांजे की खप लेते हैं और यहां सतीश सिंह द्वारा प्रयागराज व आसपास के जिलों में इस खपाया जाता है। जिसके बदले में उन्हें मोटी रकम का फायदा होता है। पूछताछ में बताया कि उनका पूरा एक गैंग है। हर जगह उनके आदमी रहते हैं। गिरफ्तारी करने वाली एसटीएफ टीम में एसआई रविंद्र कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अमित कुमार शर्मा, संतोष कुमार, रोहित सिंह, किशनचंद्र कांस्टेबल चालक अखंड प्रताप पांडेय शामिल थे।

स्वाधिकािी मुद्रक, प्रकाशक

स्वतंत्र कुमार शुक्ल (याग्यवल्क्य) द्वारा रमा प्रिंटिंग प्रेस 53/25/1–ए, बेली रोड, नया कटरा, इलाहाबाद से मुद्रित कराकर, 1269 / 1073 मां श्री आश्रम, मालवीय नगर, बाबा जी का बाग, प्रयागराज से प्रकाशित।

**–: संस्थापक –:**

स्व० श्रीकांत शुक्ल उर्फ स्वामी कांतेश्वरानंद भारती काली बाबा

**संपादक**

सतंत्र कुमार शुक्ल (याग्यवल्क्य) मोबाइल नंबर 9450475366 Email prayagdarpan@gmail.com R.N.I. NO.UPHN/2014/59804

इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पीआरबी

एक्ट के अंतर्गत उत्तरदाई तथा इनसे

उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद

न्यायालय के अधीन होंगे।